नवदुनियाँ, भोपाल
30 DEC 2016

मेरी बात

आर्थिक क्रांति की संवाहक बनी मेरे प्रदेश की जनता

शिवराज सिंह चौहान

देश में 8 नवंबर 2016 को ऐतिहासिक फैसला हुआ। इस दिन ने सरकारों के कामकाज की शैली पर जन-मानस द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों का एक सार्थक उत्तर दिया। अक्सर सरकारों पर आरोप लगते हैं कि वे कठोर निर्णय नहीं लेतीं व शक्तिशाली लोगों को नुकसान पहुंचाने से डरती हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने 500 व 1000 रुपए के नोट बंद करने का साहसिक निर्णय लेकर यह मिथक तोड़ा।

नोटबंदी का निर्णय इस मामले में भी ऐतिहासिक है कि इसने सबको चौंकाया। यही इसकी खासियत भी है। पिछले 100 साल में देश में दो बार पहले भी नोटबंदी के निर्णय लिए गए, परंतु तब लोगों को काफी समय दिया गया। ऐसे में जो लोग बड़े नोटों की शक्ल में कालाधन रखते थे, उन्हें अपना धन बदलने का पर्याप्त समय मिला। इससे उन निर्णयों के पीछे का मुख्य उद्देश्य कम सफल रहा। इस बार का निर्णय ऐसा था, जिसने लोगों को मौका नहीं दिया। आलोचकों ने कहा कि निर्णय बेहतर प्लानिंग के साथ लेना था और लोगों को पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। यह समझ से परे है कि वे किन 'लोगों' को पर्याप्त अवसर देने की बात कह रहे हैं। क्या वे गरीब जनता की बात करते हैं, जिनके पास एक समय में 5 या 10 बड़े नोटों से अधिक नहीं होते? ऐसे लोगों ने तो अपने 5-10 बड़े नोट एक ही बार में बदलवाए और निश्चिंत हो गए। तो फिर ये कौन 'लोग' हैं जिन्हें समय दिया जाना चाहिए था? स्वाभाविक है कि आलोचकों का एक वर्ग उन लोगों की हिमायत कर रहा है, जिन्होंने काले धन को नोटों के रूप में जमा कर रखा था। प्रधानमंत्रीजी का कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने का निर्णय भी देश को विकासशील से विकसित होने की दिशा में बढ़ाने वाला है।

हमारे कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दलों के मित्र कहते हैं कि नोटबंदी से किसानों को नुकसान हुआ और वे समय पर बोवनी नहीं कर सके। मप्र में स्थिति यह है कि गत वर्ष की 108 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष अब तक 105 लाख हेक्टेयर में बोवनी हो चुकी है और कुल बोवनी 115 लाख हेक्टेयर तक होगी। स्पष्ट है कि नोटबंदी से बोवनी बिलकुल प्रभावित नहीं हुई है।

नोटबंदी के तथाकथित आलोचक यह भी कहते हैं कि हमारे देश में कैशलेस लेन-देन संभव नहीं। मगर मप्र की मंडियों में नोटबंदी के बाद से 95 प्रतिशत लेनं-देन कैशलेस हो रहा है। क्या यह उनकी आंख खोलने के लिए पर्याप्त नहीं कि ऐसा वर्ग जिससे सबसे कम अपेक्षाएं थीं, वह 95 प्रतिशत लेन-देन कैशलेस कर रहा है? बीते दो माह में मप्र में अकेले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग के जरिए होने वाले लेन-देन में 77 प्रतिशत और मशीनों के जरिए होने वाली बिक्री में 54 प्रतिशत वृद्धि हुई है। क्या यह परिणाम ये इशारा नहीं करते कि देश की जनता उससे ज्यादा जागरूक और सक्षम है, जितना हमारे कतिपय आलोचक समझते हैं? कैशलेस व्यवस्था से वैट में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि पहले नकद लेन-देन से जो टैक्स चोरी होती थी, वह कैशलेस होने से कम हो रही है। इससे कर संग्रहण बढ़ेगा और राज्य सरकारें कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च कर पाएंगी।

समय की मांग है कि जनता कैशलेस लेन-देन के तरीकों में प्रशिक्षित हो। मप्र में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना में भी 10 नवंबर के बाद लगभग सात लाख नए बैंक खाते खोले और पांच लाख नए रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। मप्र सरकार ने पीओएस मशीनों पर लगने वाले वैट टैक्स और बैंकों के साथ अनुबंध पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क से छूट दी है। इससे छोटे व मध्यम व्यापारी भी आसानी से पीओएस मशीन लगा सकेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय संव्यवहार भी कैशलेस किए जा रहे हैं। टैक्स, शुल्क आदि ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। राज्य सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कृत-संकल्पित है।

मेरा विश्वास है कि आने वाला समय भारत का है और कैशलेस अर्थव्यवस्था हमें विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने में मददगार होगी।

(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)